



पश्चिम हिंद महासागर में मैडागामर के पास एक छोटा सा द्वीप है ट्रॉमलिन, वहां रहने वाला आखिरी चूहा 2005 में मार दिया गया था। फ्रांस के स्वामित्व वाले इस टापू पर संभवतया 17 वीं सदी में एक फ्रांसीसी जहाज पर चूहे यहाँ आए थे। जहाज टापू के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसमें मैलगाँसी लोग भरे हुए थे जिन्हें अगवा करके बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। युनिवर्सिटी ऑफ रीयूनियन आइलैंड के इकोलॉजिस्ट मैथ्यू ली कोर ने यह जानकारी दी। चूहों के आने से पहले यह द्वीप 8 प्रकार की सी बर्ड्स प्रजातियों का घर था, जिनमें फ्रिगेट बर्ड्स, टर्न और बूबी प्रमुख थीं। लेकिन चूहों के आने के बाद पक्षियों की आबादी घटने लगी क्योंकि चूहे पक्षियों के अंडों को खा जाते थे। सन् 2005 तक, जब फ्रांस ने चूहों का उन्मूलन शुरू किया यहाँ मात्र दो पक्षी प्रजातियाँ ही बची थीं, मास्कड बूबी और चित्र में नजर आ रही रैड फुटेड बूबी। चूहों के उन्मूलन के लगभग दो दशक के बाद आज यह द्वीप फिर से सी बर्ड्स का फलता-फूलता आवास बन गया है, अब यहाँ 7 अलग-अलग प्रजातियों के हजारों पक्षी रहते हैं। सबसे उत्साह वर्धक बात यह है कि यह द्वीप उन चन्द द्वीपों में से एक है जहाँ घुसपैटिया परभक्षी के उन्मूलन के बाद पक्षियों ने स्वतः वापसी की है। ली कोर ने हाल ही में छपे अपने शोध में इसे अद्भुत सफलता बताया है। ट्रॉमलिन आइलैंड, जो कि एक वर्ग मील से भी छोटा है, पर एक छोटे से साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर फ्रेंच अधिकारियों ने एक महीने में चूहों का खात्मा कर दिया। वर्ष 2013 तक रैड फुटेड एवं मास्कड बूबी पक्षियों की आबादी दोगुने से भी अधिक हो गई थी। इसके बाद वाइट टर्न, ब्राउन नॉडी, सूटी टर्न, वैजटेल्ड शिअरवॉटर्स एवं लैसर नॉडीज की आबादी बढ़ी है। जबकि टर्न और नॉडीज वैज टेल्ड शीअरवॉटर्स ने तो यहाँ 1856 के बाद से प्रजनन ही नहीं किया था। वैज्ञानिकों ने कहा कि परभक्षियों को हटाने के बाद ये पक्षी जल्दी रिकवरी करते हैं, पर सभी कॉलोनियों में रिकवरी नहीं हो पाती है। ट्रॉमलिन में पक्षियों की आबादी तेजी से बढ़ी है क्योंकि यहाँ जो पक्षी हैं वे तेजी से बढ़ते हैं और कहीं भी रह लेते हैं, जबकि एल्बर्ट्रॉस, पैट्रल और कुछ अन्य प्रजाति के पक्षी अपने खास स्थान के प्रति लॉयल होते हैं, वे हर साल एक ही जगह घर बनाते हैं। तथापि, शानदार रिकवरी के बाद भी इस द्वीप के पक्षियों के समक्ष कई खतरे हैं। वही खतरे, जिनका सामना विश्वभर के पक्षी कर रहे हैं।

शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में प्र.मंत्री की माफी स्वीकार करने से विपक्ष ने इनकार किया

उद्धव ठाकरे ने "सरकार को जूते मारो" रैली को लीड किया, उन्होंने कहा कि प्र.मंत्री मोदी की माफी में अहंकार की बू आ रही थी

मुम्बई, 1 सितम्बर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक ने माफी मांग ली है। प्रधानमंत्री मोदी के माफी मांगने के बाद मामला शांत होने की बजाय और गरम हो गया है।

रविवार को मूर्ति ढहने के विरोध में मुंबई में एक विशाल रैली का नेतृत्व करते हुए उद्धव ठाकरे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगी है उसमें अहंकार की भावना ज्यादा नजर आ रही थी। विपक्षी गठबंधन महा विकास अग्राड़ी के नेताओं ने मुंबई में इस विशाल रैली का नेतृत्व किया। यह रैली प्रतिष्ठित हुतात्मा चौक से शुरू होकर गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर समाप्त हुई।

प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते

वंदे भारत स्लीपर की शीघ्र मिलेगी सौगात

बेंगलुरु, 1 सितंबर (वार्ता)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि वंदे भारत के बाद भारतीय रेलवे के नक्शे पर बहुत जल्द वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का संचालन शुरू किया जायेगा और इसकी अधिकतम गति 160

■ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु रेलकारखाने में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।

किलोमीटर होगी। वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की तरह वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण भी स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। इस ट्रेन में यात्री सुरक्षा के साथ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ उद्धव ठाकरे ने रविवार को मुम्बई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक विरोध रैली को लीड किया। गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित हुई विपक्ष की सभा में उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक तरफ प्र.मंत्री मोदी इस मामले में माफी मांग रहे थे तो वहीं उनके पास में खड़े एक उप.मंत्री मुस्कुरा रहे थे। इसमें भाजपा का अहंकार साफ झलक रहा था।

■ उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सभी यहां भाजपा को भारत से बाहर करो कि मांग करने के लिए एकत्र हुए हैं भाजपा ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है उन्होंने महाराष्ट्र की आत्मा का अपमान किया है उन्हें इसके लिए सजा मिलनी ही चाहिए।

हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता से पूछा कि क्या आपने माफी में अहंकार देखा? इसमें अहंकार की बू आ रही थी, जब वह माफी मांग रहे थे तो पास में ही एक उपमुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे थे। ठाकरे ने

कहा कि ऐसी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। हम सभी यहां भाजपा को भारत से बाहर करो कि मांग करने के लिए एकत्र हुए हैं भाजपा ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है

उन्होंने महाराष्ट्र की आत्मा का अपमान किया है उन्हें इसके लिए सजा मिलनी ही चाहिए। उद्धव ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि पीएम किस बात के लिए माफी मांग रहे थे, उन्होंने इस मूर्ति का अनावरण आठ महीने पहले किया था, इतनी जल्दी मूर्ति का गिर जाना यह दिखाता है कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया था। क्या वह भ्रष्टाचार के लिए माफी मांग रहे थे?

ठाकरे ने अयोध्या के मंदिर को भी बीच में लाते हुए कहा कि भाजपा कि सरकार ने जो कुछ भी बनवाया है उसमें ही गड़बड़ हुई है, अयोध्या का राम मंदिर पहली बरसात में ही टपकने लगा, यह दिखाता है कि किस हद भ्रष्टाचार हुआ है। जोड़े मारो आंदोलन के नाम से शुरू की गई इस रैली में उद्धव ने लोगों से अपील की सीएम एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज टाली गई

मुम्बई, 1 सितम्बर कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर लगातार बढ़ रही कॉन्ट्रोवर्सी के बीच अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस और डायरेक्टर भी हैं कंगना रनौत ने हाल ही में बताया था कि फिल्म की वजह से

■ कंगना रनौत ने बताया कि फिल्म के विरोध तथा उन्हें लगातार मिल रही धमकियों की वजह से सेंसर बोर्ड ने फिलहाल फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है।

मिल रही धमकियों के बीच फिलहाल सेंसर बोर्ड ने इसे हरी झंडी देने से इनकार कर दिया है। जहां तक फिल्म की नई रिलीज डेट का सवाल है तो अभी तक इस बारे में कंगना रनौत को तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सेंसर बोर्ड को अभी इस मामले में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'तमिलनाडू को 2030 तक एक खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देंगे'

इस विज्ञान को साकार करने के लिए स्टालिन 15 दिन की यात्रा पर अमेरिका गए हैं

-लक्ष्मण वेंकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 सितम्बर। ऐसे समय पर, जब बहुत से राज्य मूलभूत मुद्दों में ही उलझे हुए हैं, तमिलनाडू अपनी मैन्यूफैक्चरिंग क्षमताओं और सामर्थ्यों का तेजी से विस्तार करने में लगा हुआ है। तमिलनाडू का विशेष ध्यान ऑटोमोटिव सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्रों पर है तथा उसकी सोच के केन्द्र में प्रविद्ध-मॉडल है।

इस मॉडल को तेजी से आगे बढ़ाने की धुन वाले मुख्यमंत्री

एम.के.स्टालिन अब एक पखवाड़े की अमेरिका यात्रा पर हैं। उनका उद्देश्य विदेशी कम्पनियों तथा मल्टी-नेशनल कम्पनियों से राज्य के लिये निवेश हासिल करना है। इससे पूर्व, वे नॉकिया, पेपल तथा माइक्रोसॉफ्ट जैसे बहुत बड़े और प्रख्यात ब्रांडों से कई एम.ओ.यू. कर चुके हैं इन एम.ओ.यू. के फलस्वरूप उच्च तथा निम्न स्तर के रोजगार सृजित होना सुनिश्चित है, जो इस समय तमिलनाडू की मूलभूत आवश्यकता है। स्टालिन 14 सितम्बर तक अमेरिका में रहकर तमिलनाडू के लिये निवेश प्राप्त करने की कोशिश

■ अमेरिका प्रवास के दौरान वे नोकिया, एपल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ब्रांड्स के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करेंगे, जिस पर पहले से ही वार्ता चल रही थी।

■ स्टालिन 14 सितम्बर तक अमेरिका में रहेंगे, इस दौरान वे राज्य के लिए भारी निवेश जुटाने का प्रयास करेंगे।

में होंगे। ये सम्भावित निवेश उनकी सरकार ने इस स्वप्न का हिस्सा है कि वे 2030 तक तमिलनाडू को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देंगे।

मैन्यूफैक्चरिंग एंड इन्वियुमेंट के लिए एक उन्नत एवं अत्याधुनिक ए.आई. चालित टेक्नॉलॉजी डेवलपमेंट सेन्टर स्थापित करेंगे। 'इन्फिक्स' नामक एक अन्य कम्पनी ने एलकॉट वाडापलानी तथा मद्रुरई में 'टेक्नॉलॉजी एंड ग्लोबल डिलीवरी सेन्टर' स्थापित करेंगे। इनमें वह 50 करोड़ रु. का निवेश करेंगी तथा 700 रोजगार सृजित होंगे। अब तक कुल मिलाकर 900 करोड़ रु. के निवेश पक्का हो गया है जिससे 4000 नौकरियाँ सृजित होंगी।

मुख्यमंत्री स्टालिन के अन्दर राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर

जबरदस्त जुनून है। वे राज्य में 39000 से अधिक फैक्ट्रियों तथा 26 लाख औद्योगिक श्रमिक देखने की बात कर रहे हैं। वे तमिलनाडू को भारत का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनाना चाहते हैं।

उनके नेतृत्व में, सरकार ने राज्य में औद्योगिक प्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए अनेक विशिष्ट पहल की हैं। उनका उद्देश्य बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करना है। उनका लक्ष्य है कि 2030 तक तमिलनाडू भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था - एक लाख करोड़ (एक ट्रिलियन) डॉलर की अर्थव्यवस्था बने।

के.सी. त्यागी ने जे.डी.यू. के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया

नयी दिल्ली, 1 सितंबर (वार्ता)। जनता दल (यूनाइटेड) :जदयू: के राष्ट्रीय प्रवक्ता के सी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। के.सी. त्यागी ने इसके पीछे बढ़ती उम्र को प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने कहा कि वे 75 वर्ष

■ के.सी. त्यागी ने इस्तीफे के पीछे का कारण अपनी बढ़ती उम्र को बताया। उन्होंने कहा कि वे 75 वर्ष के हो गये हैं तथा अब सक्रिय राजनीति करने में दिक्कत आती है।

के हो चुके हैं तथा अब उन्हीं सक्रिय राजनीति में दिक्कत हो रही है। जदयू के महासचिव आफाक अहमद खान ने एक विज्ञापन में बताया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'न्याय में देरी की परिपाटी बदलने का समय आ गया है'

राष्ट्रपति ने कहा कि जब बलात्कार जैसे मामलों में कोर्ट का फैसला एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद आता है, तो लोगों को लगता है कि न्याय की प्रक्रिया में संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है

नई दिल्ली, 1 सितम्बर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि इसके लिए अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास किए जाने की जरूरत है। जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। मुर्मू ने कहा कि "अदालतों में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति ने कहा, "कोर्ट में स्थगन की संस्कृति को बदलने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने की जरूरत है।" उन्होंने कहा कि जब बलात्कार जैसे मामलों में कोर्ट का फैसला एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद आता है, तो आम आदमी को लगता है कि न्याय की प्रक्रिया में संवेदनशीलता नहीं बची।

द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गांव के लोग तो न्यायपालिका को दैवीय मानते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ न्याय मिलता है। एक कहावत भी है- भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मगर, सवाल है कि आखिर कितनी देर? हमें इस बारे में सोचना होगा।

■ राष्ट्रपति ने जोर देते हुए कहा, जब तक किसी पीड़ित को न्याय मिलता है, तब तक तो उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी होती है। कई मामलों में उनकी जिंदगी तक खत्म हो जाती है। इसलिए हमें इस बारे में गहराई से विचार करने की जरूरत है।

■ राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि न्याय की रक्षा करना देश के सभी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अदालती माहौल में आम लोगों का स्तर बढ़ जाता है।

उन्होंने जोर देते हुए कहा, जब तक किसी पीड़ित को न्याय मिलता है, तब तक तो उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी होती है। कई मामलों में उनकी जिंदगी तक खत्म हो जाती है। इसलिए हमें इस बारे में गहराई से विचार करने की जरूरत है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि न्याय की रक्षा करना देश के सभी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अदालती माहौल में आम लोगों का तनाव का स्तर बढ़ जाता है। उन्होंने इस विषय पर अध्ययन का भी सुझाव दिया। उन्होंने महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पर भी

प्रसन्नता व्यक्त की। मालूम हो कि इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून व न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ध्वज और प्रतीक चिह्न भी जारी किया।

द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षों में जनपद स्तर पर न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, प्रशिक्षण और जनशक्ति की उपलब्धता में सुधार हुआ है। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मेरा

विश्वास है कि सुधार के सभी आयामों में तेजी से प्रगति होनी चाहिए। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि हाल के वर्षों में चयन समितियों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारण कई राज्यों में चयन समितियों में महिलाओं की संख्या में 50 की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी न्यायपालिका के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनके लिए सभी हितधारकों को मिलकर प्रयास करने होंगे। उदाहरण के लिए साक्ष्य और गवाहों से संबंधित मुद्दों को न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से मिलकर सुलझाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, यह हमारे सामाजिक जीवन का एक दुःखद पहलू है कि कुछ मामलों में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी बेखोफ घूमते रहते हैं जो लोग इन अपराधों के शिकार होते हैं वे इस डर में जीते हैं जैसे कि उनके अपने विचारों ने कई अपराध किए हों।

महिला पीड़ितों की स्थिति और भी बदतर है क्योंकि समाज के लोग भी उनका साथ नहीं देते।

आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में बाढ़, 294 गाँव खाली कराये गये

तेलंगाना में सौ से ज्यादा गाँव बाढ़ की वजह से जलमग्न हो गये हैं, आंध्र प्रदेश में 9 लोगों की मौत

नई दिल्ली, 1 अगस्त। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके कारण 5 जिलों के 294 गाँवों से 13,227 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सीनियर अधिकारियों के साथ मौसम की स्थिति की समीक्षा की। उनसे बाढ़ का आकलन करने और उसके अनुसार राहत व बचाव अभियान संचालित करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारी ने बताया कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों पर बना अनादाब रविवार तड़के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा जो कलिंगपट्टनम के पास दक्षिणी राज्य के तट को पार कर गया। इसी के कारण राज्य में पिछले दो दिनों

■ तेलंगाना की गृह मंत्री अनिता ने बताया कि बारिश के कारण 62,644 हेक्टेयर धान की फसल और 7,218 हेक्टेयर बाग जलमग्न हो गए हैं।

■ तेलंगाना में बारिश ने बीते 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कई स्थानों पर दो दिन में 27 सेन्टीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है।

से भारी बारिश हो रही थी। तेलंगाना में भारी बारिश ने जन जीवन को अस्त-व्यस्त करके रखा है। रविवार को भी तेलंगाना में बारिश अपना रौद्र रूप दिखाना जारी रखा, जिससे भयंकर बाढ़ और जलभराव की समस्या हुई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश से जूझ रहे हैं, जिससे नदियाँ उफान पर हैं, इसके कारण हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख शहरों सहित कई इलाकों में बाढ़ आ गई है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए.रेवेंत रेड्डी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए मंत्रियों के साथ आपात बैठक की। रेड्डी ने बारिश प्रभावित इलाकों की स्थिति जायजा लिया।

आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगलापुडी अनिता ने बताया कि बारिश से प्रभावित इलाकों से लोग निकाले गए, जिनके लिए एनटीआर, कृष्णा, बापटला, गुंटूर और पालनाडू जिलों में 100 राहत व पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं साथ ही 61 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)